भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या2713
जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है ।
20 अग्रहायण, 1946 (शक)

पृथक सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय का निर्माण

2713.श्री बिष्णु पद राय:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के जन प्रतिनिधि (संसद सदस्य) से दिनांक 9 अक्टूबर, 2024 के पत्र सं. एम.पी./ए.एन.आई./2024/162 के माध्यम से अंडमान और निकोबार (ए. एंड. एन.) प्रशासन के अंदर एक पृथक सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के निर्माण और आईटी संवर्गों को मजबूत करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव में सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा संबंधित हितधारकों से परामर्श अथवा अनुमोदन मांगे जाने सहित इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है;
(घ) क्या सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय की स्थापना और प्रचालन के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन को कोई वित्तिय या तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने की योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने की स्थिति में इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ)**:किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय का गठन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिए विभिन्न पहल की हैं।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) की स्थापना सरकारी सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और आधार से संबंधित सेवाओं, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान आदि सहित ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है।अंडमान एवं निकोबार में 95 सीएससी कार्यरत हैं जिनमें से 71 सीएससी जीपी स्तर पर कार्यरत हैं।

डिजिलॉकर ने नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज़ और प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच प्रदान किया है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग; भारत के महापंजीयक, अंडमान और निकोबार; राजस्व विभाग; परिवहन विभाग और अंडमान और निकोबार में 2 शैक्षणिक संस्थानों को डिजिलॉकर पर जारीकर्ता के रूप में शामिल किया गया है ।

फ्यूचरस्किल्स प्राइम, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नैसकॉम की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों में रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के अवसर प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में इन प्रौद्योगिकियों में 13 लाख से अधिक लाभार्थियों को रि-स्किलिंग/अप-स्किलिंग प्रदान करने की परिकल्पना की गई है । अंडमान और निकोबार से भी नामांकन शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ('नाइलिट') इलेक्ट्रॉनिकीएवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। भारत सरकार ने नाइलिट को मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। अंडमान एवं निकोबार में नाइलिट मान्यता प्राप्त केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिकीप्रणाली डिजाइन एवं विनिर्माण ('ईएसडीएम') के लिए कौशल विकास हेतु छात्रों का नामांकन किया है।

*****